प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
21.12.2024 / प्रादेशिक समाचार / 1945बजे

"आज के मुख्य समाचार"

- हिमाचल में जीएसडीपी की वृद्धि दर के मुकाबले राजस्व प्राप्तियां कम होने पर कैग ने उठाए सवाल–राजस्व खर्चों में 18 दशमलव 6–9 फीसदी का ईजाफा।
- मुख्यमंत्री ने कहा–प्रदेश में केवल ज़रूरत के आधार पर खोले जा रहे हैं नए संस्थान।
- एफआरबीएम रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में बढ़ते राजस्व व राजकोषीय घाटे से दबाव में हिमाचल की अर्थव्यवस्था।
- प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित।

समाचार विस्तार से.....

कैग रिपोर्ट

नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) ने प्रदेश में राजस्व प्राप्तियों व सकल घरेलू उत्पाद की बढ़ोतरी की दर में अंतर होने पर सवाल खड़े किए हैं। धर्मशाला के तपोवन में शीतकालीन सत्र के आज अंतिम दिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कैग रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्व प्राप्तियों व जीएसडीपी की बढ़ौतरी की दर में भारी अंतर को कम करने की जरूरत है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2018–19 में प्रदेश की राजस्व प्राप्तियां 14 लाख 8 हज़ार 3 सौ 83 करोड़ रुपए के मुकाबले 2022–23 में बढ़कर 19 लाख 5 हज़ार 4 सौ 5 करोड़ रुपए हो गई। कैग ने रिपोर्ट में कहा कि जीएसडीपी में बढ़ोतरी की दर 7 दशमलव 2–6 फीसदी रही, लेकिन इसी अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियों में महज 2 दशमलव शून्य–9 फीसदी की बढ़ौतरी आंकी गई है। कैग ने राजस्व प्राप्तियों की बढ़ौतरी की दर में और सुधार की जरूरत जताई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022–23 में राज्य में राजस्व प्राप्तियां 38 हज़ार 89 करोड़ 50 लाख रुपए थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार के खर्चों में वेतन, पेंशन व ब्याज के साथ–साथ उपदान पर होने वाला खर्च, कुल राजस्व खर्च 64 से 70 फीसदी है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सरकार को राजस्व प्राप्तियों में ईजाफा करने में गैर आवश्यक उपदानों में कमी लाने के साथ–साथ सतत् आर्थिक विकास व राजकोषीय सेहत को बनाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है। साथ ही कैग ने रोजमर्रा के खर्चों को पूरा करने के लिए कर्ज लेने से बचने की नसीहत भी सरकार को दी है।

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि सरकार सिर्फ नीड बेस्ड नए संस्थान खोल रही है और भविष्य में भी इसी आधार पर संस्थान खोले जाएंगे। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात कही। इस दौरान उन्होंने अगले कुछ माह के दौरान प्रदेश में एसडीएम कार्यालयों का युक्तिकरण करने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने मूल प्रश्न के उत्तर में कहा कि ज़रूरत के आधार पर सरकार ने 37 संस्थान खोल दिए हैं, जबकि एक सौ 3 संस्थान खोलने की अधिसूचना जारी कर दी गई है और इन संस्थानों के लिए नियुक्तियां की जा रही है। उन्होंने खुलासा किया कि मौजूदा

सरकार ने सत्ता में आने के बाद कुल एक हज़ार 8 सौ 65 संस्थान बंद किए हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने कई ऐसे स्कूल खोल दिए, जहां एक भी विद्यार्थी नहीं था। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने ऐसे संस्थानों का सर्वे करवाया और फिर बंद करने का निर्णय लिया गया। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधायक हंसराज के प्रतिपूरक सवाल के जवाब में कहा कि चुराह विधानसभा क्षेत्र में बिजली का मंडल खोलने के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने नेता प्रतिपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों के जवाब में कहा कि उनकी सरकार ने सिर्फ एक अप्रैल 2022 के बाद खोले गए संस्थानों को ही बंद किया है। इस मुद्दे पर राकेश जम्वाल, बिक्रम सिंह ठाकुर और अन्य ने भी प्रतिपूरक सवाल पूछे। विधायक सतपाल सिंह सत्ती के एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक व राज्य सहकारी बैंक और कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक में नए सिरे से वन टाइम सेटलमेंट योजना लाएगी।

एफआरबीएम

हिमाचल प्रदेश में बढ़ते राजस्व व राजकोषीय घाटे के साथ–साथ पेंशन व उपदानों पर होने वाले खर्च पर बढ़ोतरी से अर्थव्यवस्था पर दबाव और बढ़ा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन आज एफआरबीएम की रिपोर्ट सदन में पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में दिसंबर माह तक राजस्व घाटा बजट अनुमानों से एक हज़ार 4 सौ 93 करोड़ 25 लाख रुपए अधिक रहने का अनुमान है। राजस्व घाटा बढ़ने की वजह वेतन, पेंशन और उपदानों पर होने वाला अधिक खर्च है। एक हज़ार 4 सौ 93 करोड़ रुपए की बढ़ौतरी के साथ राजस्व घाटा बढ़कर 6 हज़ार 6 करोड़ 86 लाख तक पहुंचने का अनुमान एफआरबीएम में लगाया गया है। इसी तरह राजकोषीय घाटा 2 हज़ार 3 सौ 8 करोड़ 11 लाख रुपए की बढ़ोतरी के साथ 6 हज़ार 8 सौ 36 करोड़ 64 लाख रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। बढ़ते खर्चों के साथ–साथ प्रदेश में राजस्व प्राप्तियों का अनुमान भी गड़बड़ाया है।

सत्र समाप्त

धर्मशाला के तपोवन में आयोजित प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। चार दिन तक चले इस सत्र में कुल एक सौ 88 तारांकित और 55 अतारांकित सवाल पूछे गए। सत्र के दौरान कुल 14 सरकारी विधेयक पारित किए गए। सदन की कार्यवाही साढ़े 21 घंटे चली। विस्तृत ब्योरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट.....

——वीओ—— धर्मशाला के तपोवन में चार दिन चला विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित हो गया। ये सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक रहा क्योंकि इस दौरान पहली बार लोकसभा की तर्ज पर जहां शून्यकाल की व्यवस्था शुरू हुई वहीं नेवा यानि नैशनल ई–विधान एप्लीकेशन के लागू होने से प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही देशभर में कहीं भी देखने को मिल रही है। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने बताया कि यह सत्र प्रदेश विधानसभा के इतिहास में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि सत्र में कुल एक सौ 88 तारांकित और 55 अतारांकित सवाल पूछे गए और शून्यकाल के दौरान कुल 26 मामले विधायकों ने उठाए गए। विधानसभा सत्र के दौरान राधा स्वामी सत्संग ब्यास को राहत देने के लिए लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन विधेयक, पुलिस संशोधन विधेयक 2024 और प्रदेश सरकारी कर्मचारी भर्ती व सेवा की शर्तें विधेयक 2024 भी सदन में पारित किए गए।

धर्मशाला से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रितेश कपूर।

ओपीडी

प्रदेश उच्च न्यायालय ने अटल सूपर स्पेशिलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाना में 6 ओपीडी को फिर से खोलने के आदेश दिए हैं। एम्स चमियाना के प्रधानाचार्य ने बताया कि 23 दिसम्बर से न्यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, यूरोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी और गैस्ट्रो एंट्रोलॉजी की ओपीडी अब आईजीएमसी के बजाए चमियाना में लगेंगी।

सुनील बिट्टू

मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सहित सभी क्षेत्रों में आगे ले जाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नादौन के वार्षिक उत्सव में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने नौजवानों, किसानों, बागवानों और समाज के सभी वर्गों के लिए कई बड़ी योजनाएं आरंभ की हैं।

भुभूजोत

रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक रूप से सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भुभूजोत सुरंग, घटासनी–शिल्हा–भुभूजोत–कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ सामरिक महत्व की परियोजना के रूप में नामित करने के अनुशंसा की है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये राजमार्ग लेह–लद्दाख के लिए वैकल्पिक मार्ग के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि सामरिक महत्व के साथ–साथ इस सुरंग से क्षेत्र को सामाजिक–आर्थिक लाभ होगा और इस दृष्टि से ही परियोजना के लिए बजटीय प्रावधान किए जाएंगे।

मुख्य समाचार एक बार फिर'

- हिमाचल में जीएसडीपी की वृद्धि दर के मुकाबले राजस्व प्राप्तियां कम होने पर कैग ने उठाए सवाल–राजस्व खर्चों में 18 दशमलव 6–9 फीसदी का ईजाफा।
- मुख्यमंत्री ने कहा–प्रदेश में केवल ज़रूरत के आधार पर खोले जा रहे हैं नए संस्थान।
- एफआरबीएम रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश में बढ़ते राजस्व व राजकोषीय घाटे से दबाव में हिमाचल की अर्थव्यवस्था।
- प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित।.....